पीएम स्वनिधि के 19196 प्रकरण बैंकों में लटके

सीएस ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में जताई नाराजगी

बैंक प्रबंधकों को नोटिस जारी होंगे

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 10 जुलाई. प्रदेश के बैंक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने में अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. यदि कोई गरीब स्ट्रीट वेंडर्स बैंकों से छोटा कर्ज लेने के लिए बैंक में आवेदन देते हैं, तो ये आवेदन बैंकों में केवल धूल खाते रहते हैं, इन प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा जाता. इसी की बानगी है कि प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के थोड़े बहुत नहीं बल्कि 19196 प्रकरण बैंकों के पास लंबित है.

इस बात का खुलासा गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक के दौरान हुआ. मंत्रालय में हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग जैन ने की. इस दौरान मुख्य सचिव ने बैंकों के इस रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने इसे गैरजिम्मेदाराना करार देते हुए ऐसे बैंक प्रबंधक जिनकी बैंक शाखा में सबसे अधिक पीएम स्वनिधि के प्रकरण लंबित हैं, उन सभी को नाटिस जारी किये जाएंगे, इतना ही नहीं मुख्य सचिव ने सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण 15 दिन के भीतर करने के निर्देश भी दिये.

यहां बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को बिना ब्याज के 10 हजार रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है. यदि वेंडर समय पर ऋण राशि का भुगतान कर देते हैं तो फिर उनको एक साथ 20 हजार रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देने की पात्रता होती है. ये योजना गरीब स्ट्रीट वेंडर के व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कोविड काल में शुरू किया गया था.

> राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बैंक बिजनिस, क्रेडिट प्लान, प्रदेश में नवीन बैंक शाखाओं की अद्यतन स्थिति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, के अलावा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गयी. इस दौरान मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना का लाभ हितग्राहियों को देने के निर्देश दिये गये. मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं में इंश्योरंस क्लेम की जानकारी देने वित्तीय जागरूकता अभियान चलाने के लिए वित्त विभाग को निर्देशित किया.

फार्मासिस्ट से मत्स्य उद्यमी बनीं लवली गुप्ता

पीएम मोदी और सीएम यादव की सराहना की

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 10 जुलाई. शहर की रहने वाली लवली गुप्ता समाज के लिए प्रेरणा का काम कर रही हैं. लवली ने यह सिद्ध कर दिया कि जब संकल्प मजबूत हो और दिशा सही हो, तो कोई भी राह असंभव नहीं होती. पेशे से फार्मासिस्ट रहीं लवली ने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते फार्मा कंपनी की नौकरी छोड़ने का कठिन निर्णय लिया, लेकिन अपने आत्मबल और नई सोच से उन्होंने स्वरोजगार की राह पकड़ी.

अपने बच्चे की बीमारी के दौरान घर के करीब रहकर कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच ने उन्हें मत्स्य पालन की ओर प्रेरित किया. मछली विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लिया और अनुदान प्राप्त कर रंगीन मछलियों की यूनिट स्थापित की.

अपने पति के सहयोग से उन्होंने भोपाल और आसपास के जिलों में रंगीन मछलियों की बिक्री और एक्वेरियम की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया. आज उनकी इकाई से उन्हें लगभग 1 लाख प्रति माह की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है. यह सिर्फ उनकी सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उन सात लोगों की भी है जिन्हें उन्होंने इस कार्य से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है.

> लवली गुप्ता का यह सफर न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम किस प्रकार से आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं. लवली ने मत्स्य विभाग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था.

डिजीटल पेमेंट से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खरीदे फल

सीएम डॉ. यादव को अपने बीच देख चौंक गई जनता

सीएम डॉ. यादव ने किया ट्रैफिक नियमों का पालन

भोपाल, 10 जुलाई. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासी उस वक्त चौंक गए, जब 10 जुलाई की रात प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव अचानक उनके बीच जा पहुंचे. सीएम डॉ. यादव ने बाजार में न केवल आम जनता से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, बल्कि ठेले वाले से फल भी खरीदे. उन्होंने फल बेचने वाले को डिजीटल पेमेंट भी किया.

इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया. उनकी सादगी लोगों को पसंद आई. जनता को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी सहजता से उनके बीच खड़ा है. सीएम डॉ. यादव के इस अंदाज की लोगों ने जमकर तारीफ की.

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने चिर-परिचित अंदाज में सारे प्रोटोकॉल तोड़कर न्यू मार्केट में जनता के बीच पहुंच गए. उन्होंने यहां एक विक्रेता से खुद फल खरीदे. उन्होंने फल खरीदने के बाद तत्काल डिजिटल भुगतान भी कर दिया. उन्होंने ने ठेले वालों से उनके व्यवसाय के संबंध में बातचीत भी की. उन्होंने आम जनता का भी हालचाल जाना. बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. यादव सादगी के साथ सिर्फ दो वाहनों में बाजार पहुंचे और 15 मिनट रुक कर फल खरीदे और निवास लौट गए.

> इतना ही नहीं, लौटते समय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रेड सिग्नल पर खुद गाड़ी रोककर ट्रैफिक नियमों का पालन किया. इस तरह उन्होंने यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि कानून का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वह आम हो या विशेष. उनका सादगीपूर्ण व्यवहार प्रदेशवासियों को यह प्रेरणा देता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल उच्च पद पर बैठना नहीं, बल्कि आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना भी होता है.

विभागों में खाली पदों को भरने का काम तेजी से करें

सीएम ने बैठक में दिये निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 10 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए. रिक्त पदों पर सतत् रूप से नियुक्तियों का कार्य होने से विभागों के नियमित कार्यों में भी गति आ रही है. साथ ही वर्षों बाद पदोन्नतियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से भी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है.

वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों के कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जाए. मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है.

> इस क्रम में विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए. इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए. बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नवीन शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत करवाया.

एक फीट गड्ढों को देखो, फिर जाओ रानी कमलापति स्टेशन

राजधानी में इन दिनों सड़कों की हालत खराब है. रानी कमलापति स्टेशन के सामने की मुख्य सड़क पर बड़े गड्ढे हो गए हैं. जिसके कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका भी बढ़ी हुई है. जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है.

आरपीएफ ने तीन को बचाया

रेलवे की ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते से मिली सुरक्षा

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 10 जुलाई. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ भोपाल ने 3 नाबालिग लकडकियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है. गुरूवार को इन लडकियों को गौरवी सखी सेंटर के सुपुर्द भी किया गया.

जानकारी के अनुसार बुधवार को प्लेटफॉर्म क्रमांक 01, भोपाल स्टेशन पर सहायक उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह नियमित गश्त के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे. इस दौरान उन्होंने तीन नाबालिग बालिकाओं को डरी-सहमी अवस्था में बैठे हुए पाया. तत्क्षण उन्होंने महिला आरक्षक उमा पटेल को बुलाकर बालिकाओं को सांत्वना दी और बातचीत का प्रयास किया.

> स्थानीय यात्रियों से पूछताछ के बावजूद बालिकाओं के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी. इसके पश्चात तीनों बालिकाओं को महिला आरक्षक उमा पटेल द्वारा सुरक्षित रूप से आरपीएफ पोस्ट भोपाल लाया गया. पूछताछ में बालिकाओं ने बताया कि वे दिल्ली में अपने माता-पिता की डांट से नाराज होकर बिना किसी को बताए किसी अज्ञात ट्रेन में सवार होकर भोपाल आ पहुँची थीं.

पेट्रोल पंपों पर कमियां देखने गए अधिकारी खाली हाथ लौटे

कलेक्टर के निर्देश पर जांच दल ने की कार्रवाई

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 10 जुलाई. जिले में मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के संबंध में जांच की गई.

यह जांच राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और नापतौल विभाग के अधिकारियों ने की. कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा गठित जांच दल द्वारा चन्द्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल के निर्देश पर किया गया. जांच दल में एसपी पंडोले, नायब तहसीलदार भोपाल जगदीश भावसार, निरीक्षक नापतौल, अशोक सत्यार्थी, कुसुम अहिरवार, संदीप भार्गव, सहायक आपूर्ति अधिकारी तथा सुनिल वर्मा, पुष्पराज पाटिल, वसुंधरा पेन्ड्रो एवं मयंक द्विवेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल रहे.

जांच दल द्वारा बैरागढ़ क्षेत्र स्थित मेसर्स जनता सेल्स सर्विस, मेसर्स पंजाब सेल्स एंड सर्विस, बाहुबली सेल्स एंड सर्विस; लालघाटी स्थित मेसर्स स्मार्ट सिटी फ्यूल, नादरा बस स्टैंड हमीदिया रोड स्थित मेसर्स सलुजा सेल्स सर्विस समेत अन्य पंपों की जांच की.

पीडब्ल्यूडी मंत्री पर पटवारी ने बोला हमला

भोपाल, 10 जुलाई. सड़कों के गड्ढ़ों को लेकर मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के एक बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन पर हमलावर होते हुए कहा कि ये मंत्री का बयान नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की असफलताओं की स्वीकारोक्ति है.

पटवारी ने अपने बयान में कहा कि मंत्री सिंह का सड़कों को लेकर बयान महज बयान नहीं, भाजपा सरकार की असफलताओं की स्वीकारोक्ति है. ये गैरजिम्मेदाराना बयान प्रदेश की जनता के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. यह बयान एक मंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की संवेदनहीनता और गैरजवाबदेही

को दर्शाता है.उन्होंने कहा कि प्रमुख शहरों की हालत भयावह है. सरकार ने सड़क निर्माण और मरम्मत के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन हालात पहले से भी बदतर हैं.

पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर जाएगी. सिंह ने कल अपने बयान में सड़कों के गड्ढों को लेकर कहा था, जब तक सड़कें रहेंगी, तब तक गड्ढे होते रहेंगे. उससे मेरा मतलब ये है कि कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए चार साल हो गए, उसकी समयसीमा पांच साल है तो हो सकता है कि चार साल के बाद गड्ढे हो जाएं.

> लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है, जिसको चार साल तक खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन छह महीने में गड्ढे हो गए तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए. लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई भी ऐसी सड़क भी है जिसमें गड्ढा होता ही नहीं है तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है.

कलियासोत से मछली पकड़ने पर कार्यवाही

भोपाल. राजधानी में मत्स्य प्रजनन काल के दौरान जलाशयों की खास निगरानी रखी जा रही है. इस दौरान मछली पकड़ने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है. सहायक संचालक मत्स्योद्योग शिरीष अग्निहोत्री के निर्देशन में निगरानी दल द्वारा गुरुवार की दरमियानी रात तथा 06 जुलाई को कलियासोत जलाशय पर छापा मारकर 03 नाव एवं लगभग 3 क्विंटल वजन के जाल जब्त किये गये. अवैधानिक मत्स्याखेट चैकिंग के दौरान निगरानी दल प्रभारी उमराव सिंह कौरब मत्स्य निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे. साथ ही आगे से मत्स्याखेट न करने की चेतावनी दी गई.

अनुबंध मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली से होगी सुरक्षा

भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल ने किया समझौता

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 10 जुलाई. भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल ने ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया है. सेवा दक्षता में सुधार करने और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव को स्वचालित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में यह ठोस कदम उठाए गए है.

रेलवे ने रोलिंग स्टॉक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली (एमवीआईएस) की स्थापना के लिए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर कॉरपोरेशन

ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. एमवीआईएस एक आधुनिक, एआई/एमएल-आधारित प्रौद्योगिकी समाधान है. जो चलती ट्रेनों के अंडर-गियर के उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को कैप्चर करता है और स्वचालित रूप से किसी भी हैंगिंग, ढीले या लापता घटकों का पता लगाता है. विसंगतियों का पता लगाने पर, सिस्टम त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए वास्तविक समय के अलर्ट चेतावनी देता है..

> समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से रेलवे बोर्ड के निदेशक सुमित कुमार और डीएफसीसीआईएल के जीजीएम जवाहर लाल ने रेल भवन नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर सदस्य बी.एम. अग्रवाल, डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार और रेलवे बोर्ड तथा डीएफसीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे. एमओयू की शर्तों के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल चार एमवीआई इकाइयों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन के लिए जिम्मेदार होगा.